

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 09 नवंबर 2024, समय 1305 (5 मिनट))

केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा में चलाई जा रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान, पीएम ई-बस सेवा, शहरी सार्वजनिक परिवहन, अटल कायाकल्प एवं परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अलावा पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-शहरी सहित विकास मामलों से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई। श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह राज्यों को ज़िम्मेदारी है कि केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और इसके लिए फंड का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को समय पर भिजवाएं ताकि फंड की अगली किश्त केंद्र सरकार समय पर जारी कर सके। पीएम ई-बस सेवा परियोजना की समीक्षा करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों में ई बस परिसंचालन को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से गत वर्ष शुरू की गई इस परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 बसें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए क्लस्टर बेस पर इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अमृत योजना की समीक्षा के दौरान सम्बंधित अधिकारियों ने मंत्री को अवगत करवाया कि योजना के द्वितीय चरण के तहत जलापूर्ति एवं सीवरेज से सम्बंधित 1727 करोड़ 36 लाख रूपए की 57 परियोजनाओं को

स्वीकृति दी गई है श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ अपने मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा कर सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को केंद्रीय परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के समग्र विकास में केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन तथा सहयोग का आश्वासन भी दिया।

केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने पिछले एक दशक में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करने और विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने में हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की सराहना की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा में यह घाटा घटकर 10.8 प्रतिशत हो गया है। श्री मनोहर लाल ने राज्य की म्हारा गांव-जगमग गांव योजना की भी प्रशंसा की श्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ पुर्नोथान वितरण क्षेत्र सुधार योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विर्तन कंपनियों की एकीकृत रेटिंग और उपभोक्ता सेवा रेटिंग में सुधार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों के लिए अलग-

अलग बिजली बिल बनाए जाने का सुझाव भी किया।केंद्रीय मंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों के विभिन्न बुनियादी ढांचे के कार्यों, फंड उपयोग, स्मार्ट मीटरिंग और अन्य वित्तीय मापदंडों की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि योजना के तहत हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को 1527 करोड़ और हरियाणा बिजली वितरण निगम को 5168 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि जल्द ही गांवों के अंदर 2 लाख लोगों को 100-100 गज के भूखण्ड वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में सभी के लिए आवास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में यह भूखण्ड दिए जाएंगे, जिनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, और पार्क जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट लेने हेतु पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए बनाए गए 6 हजार 618 फ्लैट्स भी शीघ्र आवंटित किए जायेंगे।श्री नायब सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को भूखण्ड आवंटित किए गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से जल्द ही बुनियादी ढांचे के

विकास सम्बन्धी कार्यो का शुभारंभ किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए अनुमान तैयार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगाधरी के सेक्टर 23 में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के 2000 लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु भूखंड का कब्जा दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा यहां सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं।